Indian J. Soc & Pol. 03(02): 2016: 119-122 **ISSN 2348-0084 (P)**
ISSN 2455-2127 (O)

वैश्वीकरण और विकासशील देश

सत्यप्रकाश[1]
[1]अध्यक्ष, वाणिज्य संकाय, श्री महंथ रामाश्रय दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भुड़कुड़ा गाजीपुर, उ0प्र0, भारत

ABSTRACT

प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ वस्तु, सेवा, पूँजी एवं बौद्धिक सम्पदा का अप्रतिबंधित आदान प्रदान ही वैश्वीकरण कहलाता है। एक विश्वव्यापी व्यापार विधा के रुप में वैश्वीकरण एक नवीन अभिगम है। किन्तु इसकी जड़े द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद पाँच दशको में निहित है। 1960 के दशक को समाज वैज्ञानिक एवं 'नीति नियोजको' ने वृद्धि काल के रुप में देखा, 1970 को आधुनिकीकरण, 1980 के दशक को सामाजिक रुपांतरण और विकास तथा 1990 के दशक को संवहनीय विकास के रुप में व्याख्यायित किया और 20वीं सदी के समापन के दौर में उदारीकरण एवं निजीकरण पर विशेष बल देते हुए वैश्वीकरण का उदघोष किया गया। निसंदेह वैश्वीकरण ने विश्व में विकास के लिये एक माहौल तैयार किया है परंतु इसने अपने साथ अनेकानेक मुद्दों व चुनौतियों को भी जन्म दिया है। प्रस्तुत शोध पत्र में वैश्वीकरण से विशेष रूप से विकासशील देशों में उत्पन्न चुनौतियों की ओर ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया गया है।

KEYWORDS: *वैश्वीकरण, विकासशील देश, अर्थव्यवस्था, वौद्धिक संपदा*

वैश्वीकरण के उदय के कारणों में आज प्रौद्योगिकी की भूमिका अग्रणी है, यह स्वतः सिद्ध है बिना आधुनिक संसार ढांचे के ये वैश्विक तंत्र या विश्वव्यापी अर्थ व्यवस्था सम्भव नहीं होती। (वेलिश एट आल 2008, पृ 22) इसी सन्दर्भ में स्टेफन कैस्टेल्स जोर देकर कहते है कि वैज्ञानिक नवाचार विशेष रुप से सूचना तकनीकी में हुए तीव्र विकास ने भूमण्डलीय को हाथों–हाथ लिया हैं।(अहलूवालिया,2008 पृ12) वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसने वर्तमान समय में जीवन–यापन, शासन ऐश्वर्य और अभिज्ञान के नये प्रतिरुपों का निर्माण किया है। अन्य शब्दों में इसने जीवन शैली के एक नये ढंग का निर्माण किया है, वैश्वीकरण को संसार के विभिन्न लोगों, प्रदेशों और देशो के बीच बढ़ती परस्पर निर्भरता के रुप में परिभाषित किया जा सकता है, क्यों कि सामाजिक व आर्थिक सम्बन्धों ने दुनिया को बाँध दिया है।

यदि हमें किसी ऐसे मुद्दे का नाम लेने के लिए कहा जाए तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो, तो बिना विचार किसी सोच–विचार के यह 'भूमण्डलीय अथवा वैश्वीकरण' हो सकता है। वास्तव में यह एक ऐसा बहुआयामी विषय है जिसके अन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी पक्ष आ जाते है। सभी की चर्चा कही न कहीं बुनियादी तौर पर वैष्वीकरण से जुड़ जाती है।(पंत, 2008 पृ237) गिडेंस के अनुसार ''एक विशाल शक्ति के साथ भागता हुआ इंजन जिसे हम कुछ सीमा तक तो संचालित कर सकते है परन्तु इसका हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाने का भी खतरा है। इसी प्रकार आधुनिकता की संस्थाएं भी टिकी हुई है। हम इस रास्ते या गति को पूरी तरह से नियंत्रण नही कर सकते, क्योंकि वह क्षेत्र जिस पर यह इंजन चल रहा है वह गंभीर परिणामों से भरा है।(विश्वाल, 2011 पृ268) वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव से तो हर आदमी परिचित है, क्योंकि इसके कुछ छोटे मोटे संकेतक भी उपलब्ध है जैसे भारत में करोड़ पतियों की संख्या विश्व के सर्वाधिक धनाढ्य व्यक्तियों में भारतवासियों की अपनी जगह बनाना, यह सब हर्ष प्रदान करने वाली संसूचनाएं है लेकिन इससे इससे अलग भी कुछ दृश्य है जो मंथन करने को मजबूर करता है। जैसे पानी के लिए लम्बी कतारें बढ़ती हुई मंहगाई, बिजली, आवास, नालों में बदलती नदिया, कारखाने के बढ़ते प्रदूषण आदि सबकी मुख्य वजह यह है कि वैश्वीकरण से हम वही पा सकते है तो कथित विकसित देश हमें देना चाहते है।

भूमण्डलीकरण का सर्वाधिक विरोधाभास पहलू है सामाजिक आर्थिक विषमता, असमानता, सुरक्षा जो विश्व की अर्थ व्यवस्था में व्याप्त है। उत्तरी अमरीका ब्रिटेन फ्रांस, जर्मनी, इटली जो औद्योगिक अर्थव्यवस्था के रुप में आर्विभूत हुए है। पश्चिम के इन राष्ट्रों के लिए विकासशील देश लेटिन अमेरिका अफ्रीका व एशिया के देश विकल्प बाज़ार के रुप में दिखाई दे रहे है। विश्व के आर्थिक मंच के संस्थापक और अध्यक्ष क्लाज स्वाब ने विश्व व्यापार संगठन के दोहा बैठक में दिखाई दे रहा है। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक और अध्यक्ष क्लाज स्वाब ने विश्व व्यापार संगठन के दोहा बैठक में 11 सितम्बर की घटना के सन्दर्भ में बात करते हुए कहा कि ''यह भूमण्डलीकरण के खिलाफ प्रतिकूल परिस्थितियों का चरम बिन्दु था। ऐसा प्रतीत होता है कि भूमण्डलीकरण ने विकाशील विश्व में अधिकांश जनसंख्या को लाभ नहीं पहुँचाया है और पूरे विश्व में हर प्रकार की असुरक्षा तथा व्याकुलता उत्त्पन्न हो रही है।(द इकोनामिक टाइम्स 4 दिस0 2001) जबकि सामाजिक आर्थिक सम्बन्धों का विश्व तक विस्तार वैश्वीकरण है, नवीन विश्व व्यवस्था वैश्विक आर्थिक परस्पर आर्थिक निर्भरता के विकास को विवेचना करता है।(रावत, 2008 पृ151)

1: Corresponding Author

वैश्वीकरण उपभोक्ता का मूलक अर्थ व्यवस्था द्वारा अग्रसर है जबकि सम्पूर्ण विश्व का 80 प्रतिशत भाग उत्पादक मूलक अर्थ व्यवस्था में संलग्नक है। विकासशील राष्ट्रों तथा भारत में रह रहें निर्धन कमजोर वर्ग, पिछड़े वर्ग, कृषि, श्रमिक, आदि की आवश्यकताओं एवं आशाओं के लिए भ्रामक है क्योंकि यह वर्ग धनी–निर्धन वर्ग के बीच सामाजिक एवं आर्थिक दूरी को बढ़ावा देता है वैश्विकरण का कार्यक्रम पश्चिमी और उत्तर औद्योगिक संकट के उपज है। जो मानवीय संदेश एवं अनुरुपता मे सवाल से पृथक है। आज जनता से लेकर अर्थशास्त्रियों के बीच एक भ्राँति है कि हम नियोजित अर्थव्यवस्था से मुक्त बाज़ार की ओर जा रहे है। भूमण्डलीय के कारण कुछ देशों में नये प्रकार के सामाजिक तनाव भी पैदा होने लगा है। लोगो का यह मानना है कि पिछडे व विकाशसील देशों में आर्थिक व सामाजिक विषमता गहराने लगी है। हालांकि भूमण्डलीय करण के युग में कोई राष्ट्र स्वयं को इससे अलग नहीं कर सकता अपितु इससे उत्पन्न चुनौतियों से निपटने हेतु अन्य विकल्पों पर भी विचार करना चाहिए। विश्व व्यापार में गरीब देशों के उत्पादों का अमीर देशों के उत्पादों के बीच कड़ी स्पर्धा है, गरीब देशों का विश्वबाजार में हिस्सा निरन्तर घट रहा है।(विश्वाल, 2011 पृ0290)

वैश्वीकरण के सम्बन्ध में यूनीसेफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पिछड़े देशों में बच्चों की दयनीय स्थिति भविष्य में तनावों के कारण बन सकती है। यूनीसेफ का कहना है विकासशील देशों 64 करोड़ बच्चों के पास पर्याप्त बसेरा नही है। चालीस करोड़ बच्चों के पास स्वच्छ पेय जल नहीं है। 30 करोड़ सूचना से वंछित है। सत्ताइस करोड़ बच्चों को स्वाथ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं। चार करोड़ कभी स्कूल नहीं गये जबकि नौ करोड़ बच्चें बुरी तरह से अन्न से वंचित रहे। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ आवास रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला है कि तीसरी दुनिया में दयनीय आवास स्थिति के लिए भूमण्डलीकरण आर्थिक नीतियां जिम्मेदार है। अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापारी संगठन ने इन आर्थिक नीतियों को गरीब देशों पर को थोपा है। इन नीतियों के कारण ही गरीब देशों में गाँवो से शहरो की ओर लोग पलायन कर रहे है। क्योकि सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण ग्रामीण रोजगार के घटते अवसर या छिनती घरेलू जमीन, सब्सिडी, को हटाना, जैसे कारक पलायन के लिए जिम्मेदार है। रिपोर्ट यह भी मानती है कि भूमण्डलीकरण के लाभ शहरी क्षेत्रो के झुग्गी झोपड़ियों निवासियों तक नहीं पहुँच सके है। यह भी विडम्बना है कि पिछले कुछ वर्षो से भूमण्डलीयकरण की आर्थिक प्रक्रिया चल रही है लेकिन बालाश्रम में कोई कमी नहीं आयी है। तीसरी दुनिया के देशों में बड़ें पैमाने पर बालश्रम का बर्बरतापूर्वक दोहन किया जाता है।

वर्तमान आर्थिक एवं वित्तीय संकट ने उदारपूँजीवादी वैश्विक अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। इसने अमेरिका से जुड़ी प्रायः हर अर्थव्यवस्था को गंभीर रुप से प्रभावित किया हैं । आर्थिक मंदी मुख्यतःसब प्राइम रेहन अथवा गिरवी संकट का परिणाम है। इसका निहितार्थ कि उच्चतर बयान की चाहत में बिना किसी सामान्य साख के लोगो को कर्ज उपलब्ध कराना। फलतः ऐसे लोगो ने बैको से कर्ज लेना शुरु किया। जिनके पास ब्याज अदायगी का भी सामर्थ्य नहीं था, मूलधन तो दूर की बात थी। इन लोगो का साख इतनी भी अधिक अच्छी नहीं थी इनसे पैसे वसूले जा सके। फलतः कंपनियों एवं बैंको को इससे भारी आर्थिक नुकसान हुआ और अमेरिकी बाजार में गिरावट आनी शुरु हो गयी। मंदी के समय में भी लोगों में सामान्य तौर पर बचत करने,व्यय को कम करने तथा पूँजी को जमा रखने की प्रवृति पायी जाती है। फलतः उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए व्यवसायिक उद्यमों की कीमत में कमी करनी पड़ी जिसकी भरपाई इन उद्यमों ने कर्मचारियों की छटनी से की। इससे पूरे विश्व में बेरोजगारी के स्तर में वृद्धि हुई। कुल मिलाकर इन सबने एक वैश्विक संकट पैदा कर दिया है।

''व्यापारिक प्रतिस्पर्धा'' कभी भी संसार के लोगों को जोड़ने का काम नहीं कर सकती। इसका गंतव्य ही कुछ प्रतिस्पर्धियों द्वारा दूसरों को स्पर्धा से निकालना या निगलना होता है। इससे धीरे–धीरे कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठान फैल कर विशाल होते जाते है और दूसरे नष्ट होते जाते हैं या निगल लिये जाते है। आज दुनिया की लगभग साठ हजार बहुर्राष्ट्रीय कंपनियों ने संसार को अपने मकड़जाल में बाँध रखा है। यह उन्मुक्त प्रतिस्पर्धा के दर्शन और वैश्वीकरण की अर्थनीति का कमाल है कि अन्न प्रचुरता देश में वरदान के बदले अभिशाप बनी हुई है। पूँजीवादी व्यवस्था में जहाँ उत्पादन आवश्यकता के पूर्ति के लिए नहीं मुनाफे के लिए होता है।निर्बाध प्रतिस्पर्धा की नीति के कारण अमेरिका, ब्रिटेन और कई दूसरे औद्योगिक देशों में छोटे किसानों का अस्तित्व खत्म हो चुका है। विश्व स्तर पर इस नीति को बेरोक–टोक चलने का परिणाम होगा; भारत जैसे देशों की बर्बादी जिसमें प्लांटेशनों को छोड़कर बाकी सारे के सारे किसान छोटी जोतो पर निर्भर है।

अब अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण अन्तर्राष्ट्रीय सरकारी संस्थाएं IGOs कर रही है, जो अन्तराष्ट्रीय नियमों नीतियों, सिद्धान्तों और निर्णय निर्माण प्रक्रिया का संचालन करते है। इन IGOs की वैश्विक अभिशासन की भूमिका ने 'अधिकारियों या नौकरशाहों के पार सरकारी गठबंधन' का निर्माण किया है ऐसा इसलिए है क्यों कि अब नीतियों के निर्माण में निर्वाचित राज्यों या राज्य की केन्द्रीय सरकार की अधिक भूमिका नहीं रह गई है। इस वैश्वीकरण प्रवृति की एक और विशेषता है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ पर अमेरिका जैसी महाशक्तियों का प्रभुत्व है। हालांकि भूमण्डलीकरण के समर्थक व्यक्तियों एवं प्रतिष्ठानों की तरफ से यह झूठ एक स्वयं सिद्ध सत्य की तरह प्रचारित किया जा रहा है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से उन्मुक्त बाजार व्यवथा के कारण दुनिया के सभी देशों में उत्पाद व लोगों का जीवन स्तर उपर उठा है।(सिन्हा,2003 पृ101) साथ की विकास की जिस अवधारणा को हम देख रहे है जिसका उदय नई विश्व व्यवस्था के रुप में हुआ है। वास्तव में वैश्वीकरण युग के रुप में आगे बढ़ रहा है।

वैश्वीकरण और उदारीकरण के फलस्वरुप इस विश्वजनीय परस्पर निर्भरता ने न केवल राष्ट्रराज्यों की प्रभुता को निश्तेज का दिया बल्कि इसने ऐसे पेचीदा मुद्दों को जन्म दिया है जिनका हल निकालना अत्यधिक कठिन है। विश्व राजनीतिक परिदृश्य में पर्यावरण संकट, आतंकवाद, महिलाओं के कुछ मुद्दे जैसी समस्याएं उभरी है।

सुप्रसिद्व भैतिकी एवं पर्यावरणवेत्ता वन्दना शिवा वैश्वीकरण प्रक्रिया के प्रबल आलोचक है। उनके अनुसार ''वैश्वीकरण शक्तिशाली द्वारा दुर्बल पर बलपूर्वक थोपी गई एक राजनैतिक प्रक्रिया है।'' यह अल्पसंस्कृतियों पर एक विशिष्ट संस्कृति का आरोपण है। इस कथन के द्वारा न केवल आर्थिक, राजनैतिक या सांस्कृतिक क्षेत्र में विकसित देशों द्वारा शोषण की बात कर रही है। बल्कि इसमें इन्होनें हमारी पारिस्थितिकी को भी शामिल किया है। विश्व ने इसे पर्यावरणीय जाति भेद का नाम दिया है। उनके मतानुसार W.T.O. विश्वबैक IMF और जैसी विश्वव्यापी संस्थाएं इस समझौते का बदला 'प्रकृति स्त्री और तीसरी विश्व दुनिया से ले रही है। मुक्त व्यापार ने उत्तर के देशों को दक्षिण देशों में अपने विषैले अपशिष्टों का निर्यात दक्षिण को करता है। इसमें संदेह नहीं है कि पर्यावरण ह्रास के लिए वैश्वीकरण सबसे अधिक जिम्मेदार है। अमृर्त्यसेन के अनुसार– ''वैश्वीकरण के लाभ और हानियों का चिंतन करते समय न्याय की आवश्यकता के बारे में सोचना आवश्यक है। वैश्वीकरण एक उत्तम उद्देश्य है लेकिन इसके बारे में संसार के बहुत से लोगों के संदेह दूर करना काफी कठिन है। इसका अर्थ यह नहीं कि इसका उद्देश्य गलत है परन्तु इसका अर्थ यह है कि इसमें ऐसे संशोधन किये जाए यह सबको अच्छा लगे और संशोधनों के उचित विवरण के आधार पर आगे बढ़े।(वरमानी,2009 पृ131)

भारत में वैश्वीकरण की नीति अपनाने के साथ ही अनेक प्रकार के आर्थिक कार्यक्रम शुरु किये गये। इस नीति को अपनाते समय यह मान लिया गया देश में व्याप्त प्रत्येक समस्या का समाधान उदारीकरण के द्वारा ही सम्भव है। उदारी करण के प्रारम्भ होने के बाद से लेकर अब तक यदि देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि वैश्वीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर शुरु किये गये आर्थिक सुधार कार्यक्रमों का कोई सकारात्मक प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ा है इस संदर्भ में एक और बात सामने आयी है कि सुधार कार्यक्रम विदेशी दबाव यानी वैश्वीकरण से प्रेरित–प्रभावित है; इसमें कोई सन्देह नहीं कि भुगतान सन्तुलन की समस्या ने ही आर्थिक सुधारों की दिशा में तत्काल कदम उठाने के लिए बाध्य किया परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि आर्थिक सुधार हमारी जरुरत नहीं है। भारतीय अर्थशास्त्रियों ने बहुत से ऐसे सुधारों की रुप रेखा प्रस्तुत की थी, परन्तु राजनीतिक एवं अन्य वजहों से पहले तक के उन्हें लागू नहीं किया जा सकता था जबकि अन्य देशों ने उसे अपनाकर अपनी विशेष प्रगति कर ली है।

वैश्वीकरण की नीति के तहत सीमा शुल्क में कमी की गयी है। इसके दो प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़े। पहला यह कि कम सीमा शुल्क होने के कारण सरकार को सीमा शुल्क से होने वाली आय में कमी हुई है। दूसरा प्रभाव यह हुआ कि विदेशी सामान अधिक मात्रा में और कम मूल्य पर हमारे बाज़ारों में पहुँचने लगे है। भारतीय उत्पाद उसके सामने नहीं टिक पा रहे हैं। वैश्वीकरण नीति के अन्तर्गत अनेक प्रकार के सुधार आर्थिक नीतियों में किये गये है, अभी भी मजदूर कानून में कोई ऐसा मूलभूत सुधार परिवर्तन नहीं हुआ है। जबतक कानून और आर्थिक सुधार के लिए उठाये गये कदम घरेलू उद्योगों के हितो में नहीं होगे देश की उन्नति नहीं हो सकेगी। इसीलिए स्पष्ट है कि वैश्वीकरण नीति का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ हो सकता है परन्तु भारत जैसे विकासशील देशों में तो अभी तक कोई सकारात्मक प्रभाव सामनें नहीं आया है।

''आवश्यकता इस बात की है कि आर्थिक, राजनैतिक परिदृश्य को जनोन्मुख, विकासोन्मुख बनाया जाए। यह तभी संभव है जब वैकल्पिक जनशक्तियाँ उभरे।जनशक्तिकरण द्वार–द्वार पहुँचे। सत्ता के विकेन्द्रीयकरण की धाराएं गांव से होकर जायें। भूमण्डलीयकरण के सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रभावों के सम्बन्ध में जनता को जागरुक बनाया जाय। वैश्विक सामाजिक कार्यवाही को समानान्तर स्तर पर पैदा किये बगैर वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था की कल्पना करना अवास्तविक है।(गोविल,2011 पृ304)

''यदि हमें वैश्वीकरण का लाभ लेना है तो पहले हमें वित्तीय संयोजन और वित्तीय अनुशासन को सुधारना होगा। पुरानी तकनीक को भी नई तकनीक से प्रतिस्थापित करना होगा तथा सबसे बड़ी बात अपने उद्योगों को प्रोटेक्शन देना होगा। यदि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों में कार्य करने दिया जाए तथा श्रमिक कानूनो मे उचित सुधार किया जाए तो उदारीकरण का पूर्ण लाभ उठाया जा सकता है वास्तविक विकास के लिए उदारीकरण के साथ जनसामान्य की सामाजिक सुरक्षा और शान्ति आवश्यक है। देश की राजनैतिक स्थायित्व तथा राष्ट्रवादी चरित्र भी राष्ट्र की उन्नति में हमेशा सहायक होगें।(शर्मा और सिंह 2006, पृ207) हालाकि एक चीज निश्चित है कि हम वैश्वीकरण के लाभों को नहीं झुठला सकते। अतः हम वैश्वीकरण के प्रति अपने दरवाजे को बंद करने के बजाय हमें इसके लाभ एवं हानि के बीच प्रभावी सन्तुलन कायम करने का प्रयास करना चाहिए अब हम एक ऐसी स्थिति में पहुँच चुके है जहा व्यक्तिगत सरकारे कुशलता से कार्य नहीं कर सकती अतः यदि हमें वैश्वीकरण की समस्याओं से निजात पाना है तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि इसका समाधान भी वैश्वीकरण से हो सकता है। यह एक वैज्ञानिक अभिशासन के नये रुप की मांग करता है, जो सहयोग और कुशलता से वैश्विक मुद्दो का समाधान करेगा।

आवश्यकता वैश्वीकरण की समाप्ति की नहीं है। आवश्यकता इस बात की है इसके नाम पर किये जा रहे कुछ स्थानीय तथा संकीर्ण लक्ष्यों को विश्वस्तरीय आन्दोलनों द्वारा

रोका जाए। इसके लिए प्रत्यक्ष रुप से मुक्त व्यापार की नीतियों को दबाओं से मुक्त करके अपनाया तथा लागू किया जाना चाहिए। आवश्यकता इस बात की भी है कि विश्व स्तर के प्रशासन के लिए नई संरचनाओं की स्थापना की जाए साथ ही इसके नकारात्मक एवं हानिकारक प्रभावों की समाप्ति करके इसे अन्तर्राष्ट्रीय विकास तथा समृद्धि की एक उतेष्ठ प्रक्रिया बनाया जाए। वास्तव में वैश्वीकरण का प्रयास विकसित या विकासशील देशों के बीच आय की खाई को पाटने का काम कर सकता है जिससे निश्चित तौर पर प्रवास का दबाव कम होगा। साथ ही विकाशसील देशों में गरीबी कम करने, रोजगार बढ़ाने और लोगों का जीवन स्तर उठाने में मद्द मिलेगी। अतः विकसित राष्ट्रों की जिम्मेदारी है कि वैश्वीकरण की अवधारणा में पारदर्शिता के साथ आगे बढ़े जिससे कि इसमें उभरती चुनौतियों का सामना डटकर किया जा सके।

सन्दर्भ

बेलिश जान, स्मिथ स्टेन एण्ड ओनर पैटिसियल (2008) : *द ग्लोबलाइजेशन आफ वर्ल्ड पालिटिक्स, ऐन इन्टोडक्शन टू इन्टरनेशनल रिलेशन्स,* न्यूयार्क, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस,

अहलूवालिया, श्रीमंत (2008) : *ग्लोवलाइजेशन एण्ड सोशियो इकोनामिक डेवलपमेंट,* नई दिल्ली, अध्ययन पब्लिशर्स

पंत पुष्पेश, (2008) :*अन्तराष्ट्रीय संम्बन्ध,* नई दिल्ली,टाटा मैक्गाहिल पब्लिसिंग कम्पनी लिमिटेड

विस्वाल तपन, (2011) : *अन्तराष्ट्रीय संम्बन्ध* नई दिल्ली मैकमिलन पब्लिकेशन,

श्वाब '11सितम्बर की घटनाओं ने विश्व को बदल दिया, *द इकोनामिक टाइम्स* 04 दिसम्बर 2001

रावत, हरिकृष्णा (2008) : *इनसाइक्लोपीडिया आफ सोशियोलाजी,* जयपुर, रावत पब्लिकेशन्स

सिन्हा सच्चिदानंद, (2003) : *भूमण्डलीकरण की चुनौतियाँ,* दरियागंज, नई दिल्ली, वाणी प्रकाशन

येरेडे, वी एल (2013) : *इन्टरनेशनल पालिटिक्स,* नई दिल्ली, चन्द्रलोक पब्लिकेशन्स

वरमानी, आर0सी0 (2009) : *वैश्वीकृत संसार में नागरिता,* नई दिल्ली, गीतान्जली पब्लिशिंग हाउस

गोविल, आर0के0 एस दयाल, (2014) : *कृषि अर्थ शास्त्र,* आगरा, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल

शर्मा टी0आर0, वार्ष्णेय सिंह, (2006) : *विकास का अर्थशास्त्र एवं नियोंजन* आगरा, साहित्य भवन पब्लिकेशन